Shortage of Potable Water in Rural Areas of Karnataka

6506. SHRI JANARDHAN POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of potable water in the rural areas of Karnataka;

(b) if so, the number of villages that are facing such a problem as on 30th April, 1995; and

(c) the steps Government have taken/ propose to take to solve the problem?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) No such report has been received from the State Government of Karnatka.

(b) and (c) Question does not arise.

कपार्ट द्वारा प्रदान की गई धनराशि से लखनौर प्रखण्ड में निर्मित शौचालय

6507. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या प्रधान मंत्री 22 दिसम्बर, 1994 के राज्यसभा में अतारांकित प्रश्न 2692 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लखनौर प्रखण्ड में उन स्थानों के नाम, परिवार के प्रमुख व्यक्ति का नाम तथा पता क्या है जहां लोक कार्यक्रम तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) द्वारा प्रदान की गई धनराशि से 419 तथा 467 शौचालयों का निर्माण किया गया है; और

(ख) इनमें से कार्यरत और अकार्यरत शौचालयों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) व (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

World Bank Assistance for Implementation of State Marketing Board Schemes

6508. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:
SHRI AAS MOHAMMAD:
SHRI AJIT P.K. JOGI:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether any financial assistance has been received is likely to be received from the World bank for implementing the Stae Marketing Board Schemes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Ministry of Rural Areas and Employment have issued and directions to various States for implementing this scheme; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Project in Saurashtra region to provide self-employment to SCs/STs

6509. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE:
SHRI CHIMANBHAI HARIBHAI SHUKLA:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the projects is Saurashtra region to provide self-employment to Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) the number of students to whom self-employment opportunity has been provided through these projects during the last three years, year-wise; and

(c) the assistance given for these projects during the last three years, year-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) The scheme of TRYSEM (Training of Rural Youth for Self Employment) is being implemented in the entire State of Gujarat and the Central Share of funds are released for the State as a whole and not Districtwise. The assistance to the State is provided on 50:50 basis.

(b) and (c) Physical and financial progress of the Scheme during the last three years in the State of Gujarat is indicated as under:

Year	No. of trained youth self employed	Central Assistance released (in lakh)
1992-93	4168	102.65
1993-94	3382	157.24
1994-95	2876 (upto Feb. 1995)	195.67

गुजरात में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की योजना

6510. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:**
श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गुजरात में स्वच्छ पेयजल का कम से कम एक स्त्रोत उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, जिलावार, ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में अनुमानत: प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने पेयजल की आवश्यकता होती है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) जी हां।

(ख) योजनाओं की जिला-वार आयोजना और कार्यान्वयन राज्य स्तर पर किया जाता है।

(ग) वर्तमान मानदण्ड 40 लिटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का है।

गुजरात में ट्राइसेम कार्यक्रम की उपलब्धियां

6511. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में गुजरात के बड़ोदरा, भरुच, सूरत, अहमदाबाद और पंचमहाल जिलों में ट्राइसेम कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त जिलों में इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले है और उक्त जिलों में इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये क्या दिशानिर्देश जारी किये गये है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) ट्राइसेम कार्यक्रम राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों जो अपनी समग्र उपलब्धियों को पूरे राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए भेजते हैं न कि जिलावार, की मार्फत कार्यान्वित किया जा रहा है। गुजरात राज्य में गत 3 वर्षों के दौरान ट्राइसेम कार्यक्रम की उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) ट्राइसेम कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए जून से अगस्त 1993 के दौरान 10 राज्यों में "ट्राइसेम का शीघ्र मूल्यांकन" कराया गया था। उपरोक्त मूल्यांकन के अंतर्गत गुजरात राज्य के चार जिलों अर्थात बनासकांठा भड़ौच, डांग और सुरेन्द्रनगर को कवर किया गया था। गुजरात राज्य में मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:—

(1) गुजरात राज्य में छोटे स्तर पर क्षेत्र दक्षता सर्वेक्षण करवाया गया था।

(2) ट्राइसेम प्रशिक्षण के बाद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार के आधार पर लाभार्थियों का प्रतिशत वितरण 17.50 प्रतिशत था।